

उम्मीद

10 महीने बाद कल होगी डीजीएफटी व एयरपोर्ट संचालन से जुड़े सदस्यों की बैठक

एक्सपोर्ट ई कॉमर्स हब के निर्माण को मिलेगी रफ्तार

आशीष गुप्ता

लखनऊ। शहर व प्रदेश से निर्यात कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट के पास ई कॉमर्स हब बनना प्रस्तावित है। पिछले साल हुई बैठक के बाद अब इसकी फाइल आगे बढ़ रही है। जिला प्रशासन की मदद से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में पिछले साल तत्कालीन डीएम ने रुचि दिखाते हुए एक्सपोर्ट कमेटी की बैठक में इसे मंजूरी दी थी। 18 सितंबर को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) व एयरपोर्ट संचालन से जुड़े लोगों की बैठक बुलाई है।

पिछले साल दिसंबर 2024 में इस दिशा पहल शुरू हुई थी। एक्सपोर्ट कमेटी की बैठक में निर्यातकों के प्रस्ताव पर तत्कालीन डीएम सुर्यपाल गंगवार ने प्रोजेक्ट पर सहमति जताते हुए इसे मंजूरी दी थी। डीजीएफटी व एयरपोर्ट अथॉरिटी के

दिसंबर 2024 में एक्सपोर्ट कमेटी की बैठक में तत्कालीन डीएम ने दी थी मंजूरी

लखनऊ एयरपोर्ट के पास बनना है एक्सपोर्ट ई-कॉमर्स हब, प्रदेश से बढ़ेगा निर्यात

अफसरों से बातचीत भी की थी। लेकिन, शासन में उनके प्रमोशन के बाद जिला एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी की सिर्फ एक बैठक अप्रैल में हुई। इससे प्रोजेक्ट को रफ्तार नहीं मिल सकी। नई बैठक से फिर निर्यातकों में उम्मीद जगी है।

निर्यातक मंसूर नदीम लारी बताते हैं कि प्रदेश सरकार से एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 10 करोड़ रुपये देने की मांग की गई थी। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसी के तहत जिला

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों वाले एयरपोर्ट के पास बनना है हब

निर्यात कारोबार बढ़ाने के लिए डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) ऐसे बड़े शहर जहां के एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं, उन एयरपोर्ट के पास ई-कॉमर्स हब बनाने की मंजूरी दी थी। अभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में ई-कॉमर्स हब बनाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की कनेक्टिविटी के मामले में लखनऊ उत्तर भारत में दूसरे तो देश में नौवें स्थान पर है। लिहाजा, प्रदेश में एक ही हब और वह भी लखनऊ एयरपोर्ट के पास बनना है।

आगे की रणनीति पर होगी चर्चा

एक्सपोर्ट ई कॉमर्स हब के मामले में डीएम विशाख जी ने बताया कि बैठक में पुरानी समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में संयुक्त रूप से डीजीएफटी और एयरपोर्ट एक्जीक्यूशन की टीम भी शामिल होगी। उपायुक्त उद्योग मनोज चौरसिया ने बताया कि 18 सितंबर को बैठक बुलाई गई है।

प्रशासन को भी लखनऊ में एक्सपोर्ट ई कॉमर्स हब बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। कहा कि सरकार के साथ निर्यातक मिलकर काम करेंगे। इससे छोटे छोटे उद्यमियों को भी अपना उत्पाद विदेश में बेचने में आसानी

होगी। हब में कस्टम क्लियरेंस से लेकर निर्यात से जुड़ी अन्य कार्रवाई भी हो सकेंगी। हब के वेयरहाउस में सामान रखने के साथ-साथ पैकेजिंग, लेबलिंग आदि की भी व्यवस्था होती है। (संवाद)